



3 June, 2023

भारत में बीमा विस्तार और बीमा वाहक

संदर्भ: भारत के बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने भारत में बीमा जाल में सुधार के लिए बीमा वाहकों के लिए मसौदा दिशानिर्देश जारी किए हैं।

IRDAI (भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण) ने ग्रामीण क्षेत्रों में बीमा जागरूकता और स्वीकार्यता में सुधार लाने के उद्देश्य से एक समर्पित वितरण चैनल, बीमा वाहक के लिए दिशानिर्देशों का मसौदा प्रस्तावित किया है।

- बीमा वाहक आईआरडीएआई के "2047 तक सभी के लिए बीमा" हासिल करने के लक्ष्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
- यह प्रत्येक ग्राम पंचायत (भारत में स्थानीय स्व-शासन संस्थान) तक पहुंचकर, बीमाकर्ताओं के लिए अंतिम-मील संपर्क के रूप में काम करेगा।
- वितरण चैनल में एक फील्ड फोर्स जिसमें कॉर्पोरेट और व्यक्तिगत बीमा वाहक दोनों शामिल होंगे, जिनमें मुख्य रूप से महिलाएं होंगी।
- इसका उद्देश्य स्थानीय लोगों के बीच विश्वास पैदा करना और बीमा उत्पादों के वितरण और सर्विसिंग को सक्षम बनाना है।
- बीमाकर्ता बीमा वाहकों के माध्यम से प्राप्त नीतियों के लिए केवाईसी (अपने ग्राहक को जानें) और एएमएल (धन शोधन निवारण) अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे।
- मसौदा दिशानिर्देश 22 जून तक टिप्पणियों के लिए खुले हैं।
- बीमा वाहक से प्रत्येक ग्राम पंचायत में व्यापक कवरेज प्रदान करने और वित्तीय सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पेशकशों को अनुकूलित करके बीमा समावेशन को बढ़ाने की उम्मीद है।

बीमा वाहक कौन हैं?

IRDAI के अनुसार, प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक 'बीमा वाहक' होगा, जिसे स्वास्थ्य, संपत्ति, जीवन और व्यक्तिगत दुर्घटना को कवर करने वाले बीमा विस्तार नामक साधारण पैरामीट्रिक बंडल बीमा उत्पादों, को बेचने और सेवा देने का काम सौंपा जाएगा।

भारत में बीमा क्षेत्र

- उभरते हुए बीमा बाजारों में, भारत 32-34% की दर से बढ़ते हुए पाँचवें सबसे बड़े जीवन बीमा बाजार के रूप में उभरा है।
- उद्योग में कुल 57 बीमा कंपनियां हैं, जिनमें 24 जीवन बीमा पर और 34 गैर-जीवन बीमा पर केंद्रित हैं।
- सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी, जीवन बीमा निगम (एलआईसी) का जीवन बीमा क्षेत्र में एकाधिकार है।
- गैर-जीवन बीमा खंड में, छह सार्वजनिक क्षेत्र के बीमाकर्ता हैं।
- भारतीय जेनेरल बीमा निगम (GIC Re) एकमात्र राष्ट्रीय पुनर्बीमाकर्ता के रूप में कार्य करता है।

बीमा घनत्व:

- बीमा घनत्व कुल जनसंख्या के लिए बीमा प्रीमियम का अनुपात है। यह इस बात का संकेत देता है कि देश में प्रत्येक व्यक्ति प्रीमियम के रूप में बीमा पर कितना खर्च करता है।
- बीमा घनत्व ने ऊपर की ओर रुझान दिखाया, जो 2020-21 में 78 अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2021-22 में 91 अमेरिकी डॉलर हो गया।

बीमा पहुँच/स्वीकार्यता :

- बीमा स्वीकार्यता किसी देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में बीमा प्रीमियम के योगदान को प्रतिशत के रूप में मापता है।

डीम्ड विश्वविद्यालयों के लिए UGC के नए दिशानिर्देश

संदर्भ: शिक्षा मंत्रालय ने भारत में डीम्ड विश्वविद्यालयों के लिए दिशानिर्देशों का नया सेट जारी किया है।

नई गाइडलाइंस के मुख्य बिंदु

- शासन संरचना केंद्रीय विश्वविद्यालयों के समान होगी।
- कम से कम 5 विभागों वाले बहु-विषयक संस्थान या एक ही शहर / कस्बे में स्थित न्यूनतम 5 विभागों वाले संस्थानों का समूह डीम्ड विश्वविद्यालय के दर्जे के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- योग्यता मानदंड में लगातार तीन कालक्रम के लिए 3.01 सीजीपीए के साथ एनएएसी 'ए' ग्रेड, लगातार तीन कालक्रम के लिए पात्र कार्यक्रमों के दो-तिहाई के लिए एनबीए मान्यता, या एनआईआरएफ रैंकिंग में विशिष्ट श्रेणियों के शीर्ष 50/100 में स्थान प्राप्त करना शामिल है।
- "डी नोवो" श्रेणी को "विशिष्ट संस्थान" श्रेणी से बदल दिया गया है, जिसमें अद्वितीय विषयों, सामरिक आवश्यकताओं, सांस्कृतिक विरासत, पर्यावरण, कौशल विकास, खेल, भाषाओं आदि पर ध्यान केंद्रित करने वाले संस्थान शामिल हैं।
- एनआईआरएफ की "विश्वविद्यालयों" श्रेणी में एनएएसी 'ए' ग्रेड या विश्वविद्यालय रैंकिंग में शीर्ष 1-100 वाले विश्वविद्यालयों को ऑफ-कैंपस केंद्र खोलने की अनुमति देता है।
- शिक्षा मंत्रालय (MoE) द्वारा पिछली अनुमोदन प्रक्रिया की जगह, यूजीसी द्वारा ऑफ-कैंपस केंद्रों के लिए एक प्रस्ताव दिया जाएगा।

Face to Face Centres





3 June, 2023

- डीम्ड विश्वविद्यालय UGC के नियमों के अनुसार **off-shore campus** केंद्र स्थापित कर सकते हैं।
- एनएएसी ग्रेड 'ए' से कम या एनआईआरएफ में 100 से ऊपर रैंकिंग वाले संस्थानों के लिए यूजीसी द्वारा निगरानी और कमियों में सुधार किया जाएगा।
- सरकारी परीक्षण एजेंसी या डीम्ड विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा में योग्यता के आधार पर ही प्रवेश होंगे।
- शुल्क रियायतों और छात्रवृत्ति के प्रावधानों के साथ, गैर-मुनाफाखोरी/गैर-वाणिज्यिक पहलुओं पर विचार करते हुए शुल्क निर्धारण पारदर्शी होना चाहिए।
- आरक्षण भारत के संविधान और संसद के लागू कानून के अनुरूप होना चाहिए।
- डीम्ड विश्वविद्यालय यूजीसी के नियमों के अनुसार ऑनलाइन/दूरस्थ पाठ्यक्रम/डिग्री प्रदान कर सकते हैं।
- शिक्षाविदों, प्रशासन, वित्त, या अन्य विश्वविद्यालय कार्यों के संबंध में शिकायतों के जवाब में सरकार या यूजीसी द्वारा पूछताछ/निरीक्षण किए जा सकते हैं।
- डीम्ड विश्वविद्यालय खाते प्रायोजक निकायों से अलग होने चाहिए, और धन का उपयोग पूरी तरह से विश्वविद्यालय के उद्देश्यों के लिए किया जाना चाहिए।
- यूजीसी के नियमों के उल्लंघन के लिए चेतावनी, कार्यक्रम/विभाग बंद करने और डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा वापस लेने सहित वर्गीकृत दंड लागू किए गए हैं।
- मौजूदा डीम्ड विश्वविद्यालयों को भी इन नियमों का पालन करना होगा।

डीम्ड विश्वविद्यालय क्या है?

डीम्ड यूनिवर्सिटी, जिसे डीम्ड-टू-बी-यूनिवर्सिटी के रूप में भी जाना जाता है, DHE (उच्च शिक्षा विभाग) द्वारा भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों को दी गई मान्यता है। UGC (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग) की सिफारिश पर, यह दर्जा MoE (शिक्षा मंत्रालय) के तहत प्रदान की जाती है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग:

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) भारत सरकार के अधीन एक वैधानिक निकाय है।
- यह भारत में उच्च शिक्षा के मानकों के समन्वय, निर्धारण और प्रतिपालन के लिए जिम्मेदार है।
- यूजीसी की स्थापना 1956 में संसद के एक अधिनियम द्वारा की गई थी।
- इसके प्राथमिक कार्यों में विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को अनुदान देना, विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए दिशानिर्देश तैयार करना और उनके कामकाज की निगरानी करना शामिल है।
- यूजीसी विश्वविद्यालयों में अनुसंधान और विकास को भी बढ़ावा देता है और छात्रों को छात्रवृत्ति और फेलोशिप प्रदान करता है।
- यह विश्वविद्यालयों को मान्यता देने और उच्च शिक्षा में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है।
- देश में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता और प्रासंगिकता बढ़ाने के लिए विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और अन्य हितधारकों के साथ मिलकर काम करता है।

विश्व बैंक

प्रसंग: भारतीय मूल के श्री अजय बंगा ने विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है।

- अजय बंगा 2 जून को विश्व बैंक के अध्यक्ष बन गए हैं।
- वह भारतीय मूल के हैं और उनकी नियुक्ति को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत की उपस्थिति के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण के रूप में देखा जा रहा है।
- हालांकि श्री बंगा एक अमेरिकी नागरिक हैं और राष्ट्रपति जो बिडेन द्वारा इस भूमिका के लिए चुने गए थे, वे पहले एक भारतीय नागरिक थे और उन्हें 2016 में पद्म श्री पुरस्कार मिला था।
- परंपरागत रूप से, विश्व बैंक की अध्यक्षता संयुक्त राज्य अमेरिका के एक नामित व्यक्ति द्वारा की जाती रही है।
- निवर्तमान अध्यक्ष, डेविड मलपास को डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा नियुक्त किया गया था और कथित तौर पर बिडेन प्रशासन का विश्वास खो दिया, जिसका उद्देश्य विश्व बैंक के दायरे में सुधार और विस्तार करना है।



Fig. 4.1 The World Bank Group

Face to Face Centres





विश्व बैंक

- विश्व बैंक ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के परिणामस्वरूप 1944 में स्थापित एक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्था है।
- इसमें पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतरराष्ट्रीय बैंक (IBRD) और अंतरराष्ट्रीय विकास संघ (IDA) शामिल हैं।
- बैंक का उद्देश्य गरीबी को कम करना और साझा समृद्धि को बढ़ावा देना है।
- यह विकासशील देशों को वित्तीय सहायता, नीतिगत सलाह और तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान करता है।
- विश्व बैंक के अध्यक्ष की नियुक्ति कार्यकारी निदेशक मंडल द्वारा की जाती है।
- बैंक संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों सहित विभिन्न वैश्विक पहलों का समर्थन करता है।
- परिचालन दक्षता बढ़ाने और प्रतिनिधित्व और पर्यावरण संबंधी चिंताओं जैसी चुनौतियों का समाधान करने के लिए सुधार किए जा रहे हैं।
- विश्व बैंक का काम बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, जलवायु परिवर्तन और सामाजिक समावेश जैसे क्षेत्रों पर केंद्रित है।
- इसकी सहायता में ऋण, अनुदान और गारंटी शामिल हैं।
- बैंक सतत विकास उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सदस्य देशों और हितधारकों के साथ सहयोग करता है।
- प्रमुख रिपोर्ट:
 - ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (प्रकाशन बंद)।
 - मानव पूंजी सूचकांक।
 - विश्व विकास रिपोर्ट।
- संयुक्त राज्य अमेरिका 16.41% वोटों के साथ सबसे बड़ा एकल शेयरधारक है, इसके बाद जापान (7.87%), जर्मनी (4.49%), यूनाइटेड किंगडम (4.31%), और फ्रांस (4.31%) का स्थान है। शेष शेयर अन्य सदस्य देशों के बीच विभाजित हैं।
- विश्व बैंक विकासशील देशों की सहायता पर ध्यान केंद्रित करता है, जबकि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) का प्राथमिक लक्ष्य वैश्विक मौद्रिक प्रणाली को स्थिर करना और वैश्विक मुद्राओं की देखरेख करना है।

NEWS IN BETWEEN THE LINES

भारतीय कुश्ती संघ (WFI)

संदर्भ: WFI प्रमुख पर हाल के आरोपों ने इस निकाय को सुर्खियों में ला दिया है।

- रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (WFI) भारत में कुश्ती के लिए शासी निकाय है।
- इसे 1964 में स्थापित किया गया था और यह यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग (UWW) और भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) से संबद्ध है।
- WFI राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न कुश्ती प्रतियोगिताओं का आयोजन और नियमन करता है।
- ओलंपिक खेलों और राष्ट्रमंडल खेलों सहित अंतरराष्ट्रीय दूरामेंटों में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए पहलवानों को चुनने और मैदान में उतारने के लिए जिम्मेदार है।
- WFI विभिन्न भार वर्गों में प्रतिभाशाली पहलवानों की पहचान करने के लिए राष्ट्रीय चैंपियनशिप, ट्रायल और चयन शिविर आयोजित करता है।
- यह कुश्ती प्रतियोगिताओं के लिए नियमों और विनियमों को लागू करता है और निष्पक्ष खेल और एथलीट सुरक्षा सुनिश्चित करता है।

सामरिक पेट्रोलियम भंडार

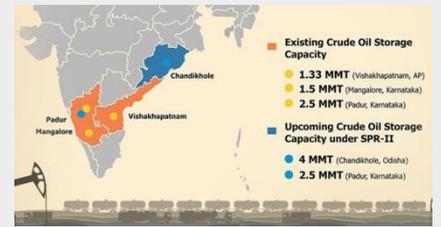
संदर्भ : राज्य संचालित इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड (EIL) राजस्थान में बीकानेर के पास भूमिगत नमक-गुफा आधारित सामरिक कच्चे तेल रिजर्व विकसित करने की संभावना तलाश रहा है।

सामरिक पेट्रोलियम भंडार: रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार प्राकृतिक आपदाओं, युद्ध या अन्य आपदाओं से कच्चे तेल आपूर्ति बाधित होने के जोखिम से संबंधित किसी भी संकट से निपटने के लिए कच्चे तेल के विशाल भंडार हैं।
तीन स्थानों पर रणनीतिक कच्चे तेल के भंडार हैं -

- विशाखापत्तनम,
- मैंगलोर और
- पादुर (उडुपी के पास)।

सरकार ने चांदीखोल (ओडिशा) और पादुर (कर्नाटक) में दो अतिरिक्त सुविधाओं की स्थापना के लिए भी मंजूरी दे दी है।

सामरिक कच्चे तेल भंडारण सुविधाओं का निर्माण भारतीय सामरिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड (ISPRL) द्वारा प्रबंधित किया जा रहा है, जो एक विशेष उद्देश्य वाहन (SPV) है, जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत तेल उद्योग विकास बोर्ड (ओआईडीबी) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है।



Face to Face Centres





3 June, 2023

<p>अनुच्छेद 371C</p>	<p>संदर्भ: पहाड़ी क्षेत्रों में मैती की बसावट को लेकर हाल ही में हुई झड़पों ने अनुच्छेद 371C को सुर्खियों में ला दिया है अनुच्छेद 371 C मणिपुर राज्य के लिए विशेष प्रावधान से संबंधित है। इसके कुछ प्रमुख प्रावधान हैं:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ अनुच्छेद 371 C जो कि भाग XXI में शामिल है, 1971 के 27वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से शामिल किया गया था। ➤ यह राष्ट्रपति को मणिपुर विधान सभा में एक समिति स्थापित करने का अधिकार है, जिसमें राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों से चुने गए सदस्य शामिल हैं। ➤ शब्द "पहाड़ी क्षेत्र" उन क्षेत्रों को संदर्भित करता है जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा एक आदेश के माध्यम से नामित किया गया है। ➤ राष्ट्रपति उपरोक्त समिति के प्रभावी कामकाज को सुनिश्चित करने की विशिष्ट जिम्मेदारी राज्यपाल को भी सौंप सकता है। ➤ राज्यपाल को पहाड़ी क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित एक वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। ➤ केंद्र सरकार के पास पहाड़ी क्षेत्रों के शासन के संबंध में राज्य सरकार को निर्देश जारी करने का अधिकार है।
<p>आईएनएस त्रिशूल</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ संदर्भ: INS त्रिशूल ने नौसेना की लंबी दूरी की तैनाती के एक भाग के रूप में कोमोरोस का दौरा किया। ➤ भारतीय नौसेना के तलवार वर्ग का दूसरा फ्रिगेट -आईएनएस त्रिशूल (F43), 2003 में कमीशन किया गया था। ➤ जहाज का नाम " त्रिशूल " रखा गया था और भारतीय नौसेना के शस्त्रागार में शामिल हो गया। ➤ कमीशनिंग समारोह 25 जून 2003 को रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में पश्चिमी नौसेना कमान में हुआ था। ➤ आईएनएस त्रिशूल में 32 अधिकारियों और 228 नाविकों का दल है।
<p>कोमोरोस</p>	<p>राजधानी: मोरोनी क्षेत्र: कोमोरोस पूर्वी अफ्रीका के क्षेत्र में स्थित है। पड़ोसी देश : कोमोरोस निम्नलिखित देशों से घिरा हुआ है : उत्तर पश्चिम: तंजानिया पूर्वोत्तर: मैयट (फ्रांस का विदेशी विभाग) दक्षिण: मोज़ाम्बिक चैनल (हिंद महासागर)</p> 
<p>खबरों में स्थान</p>	<p>जिगुइनचोर संदर्भ : सेनेगल शहर में दो राजनीतिक दलों के बीच झड़प में कई लोगों की मौत हो गई।</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ राजधानी: डकार ➤ क्षेत्र : सेनेगल पश्चिम अफ्रीका के क्षेत्र में स्थित है। ➤ पड़ोसी देश : सेनेगल निम्नलिखित देशों के साथ सीमा साझा करता है: <ul style="list-style-type: none"> • उत्तर: मॉरिटानिया • पूर्व: माली • दक्षिण पूर्व: गिनी • दक्षिण पश्चिम: गिनी-बिसाऊ • पश्चिम: गाम्बिया 

